यू० पी० बैंक इम्प्लाईज यूनियन

पंजीकरण संख्या–538
ए.आई.बी.ई.ए. से संबद्ध
केन्द्रीय कार्यालय : 106/107 द्वितीय तल, ब्लाक संख्या 26/2/4, संजय प्लेस, आगरा–282002
पत्र व्यवहार : 3/17, विभव नगर, आगरा–282 001, मो0: 09837472750
फोन/फैक्सः (नि0) 0562–4044383, **E-mail: mmrai_2509@yahoo.co.in & mmrai2509@gmail.com**

परिपत्र संख्या : 2019–22/51/2020 **दिनांक :** 28.03.2020

सभी प्रान्तीय पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों
जिला इकाईओं के मंत्रियों/अध्यक्षों हेतु

प्रिय साथियों,

वित मंत्री द्वारा घोषित राहत पैकेज

कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए वित्त मंत्री द्वारा घोषित राहज पैकेज के विषय में एआईबीईए केन्द्रीय कार्यालय द्वारा परिपत्र संख्या 28/182/2020/20 दिनांक 27.3.2020 जारी किया गया है। हम इस परिपत्र का अनूदित सार अपनी सभी इकाईओं एवं सदस्यों की सूचना एवं संज्ञान हेतु नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं।

अभिवादन सहित,
आपका साथी,

(मदन मोहन राय)
महामंत्री

प्रिय साथियों,

कोविड19 – वित्त मंत्री द्वारा घोषित राहज पैकेज पर्याप्त नहीं – बहुत अधिक की आवश्यकता है

वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा राहज पैकेज के रूप में कल विभिन्न उपायों की घोषणा की गई है, जो कोरोना वायरस के प्रसार के खतरे के परिणामस्वरूप उत्पन्न आर्थिक चुनौतियों को पूरा करने के लिए निर्देशित है। वित्त मंत्री द्वारा रू0 1.7 लाख करोड़ की राशि की राहत की घोषणा हमारी जीडीपी का केवल 0.80% है। यह आवश्यकता की तुलना में और अन्य देशों ने जो किया है उसकी तुलना में भी कहीं कम राहत है।

भारत की विशाल आबादी और कोविड19 के कारण स्वास्थ्य जोखिम की उच्च दर को देखते हुए, इसका हमारे देश में व्यापक सामाजिक और आर्थिक प्रभाव पड़ेगा।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत घोषित राहत और प्रोत्साहन पैकेज में नकद अंतरण, खाद्य सुरक्षा पर उपाय, गरीबों को मुफ्त रसोई गैस और स्वास्थ्यकर्मियों के लिए रू0 50 लाख का बीमा कवर शामिल है। इन उपायों की घोषणा कुछ समय पहले की जानी चाहिए थी। इसके अलावा राहत राशि न केवल छोटे व्यवसायों की तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल है, बल्कि दुनियाभर में अन्य सरकारों द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर उपायों की तुलना में भी कम है।

आईएमएफ (पॉलिसी ट्रैकर) द्वारा डाले गए आंकड़े, जो 24 मार्च तक दुनिया भर में प्रमुख आर्थिक प्रतिक्रियाओं का सार प्रस्तुत करते हैं, सुझाव देते हैं कि भारत अन्य देशों की तुलना में राजकोषीय और मौद्रिक नीति दोनों उपायों पर आलेख के पीछे है। भारत का 21 दिन का देशव्यापी लॉकडाउन, हालांकि, अधिक कड़े नियंत्रण उपायों में से एक है।

जारी पृष्ठ 2

लॉकडाउन, जिसने राज्यों में माल और लोगों की आवाजाही को प्रभावित किया है, पहले से ही भोजन और सब्जियों की कमी का कारण बन गया है। बैंक भी अधिकांश शाखाओं को बंद करने की योजना बना रहे हैं, जिससे आने वाले हफ्तों में आम आदमी के लिए और अधिक मुसीबत हो सकती है। इसके आलोक में, केन्द्र का राहत पैकेज गरीबों को बहुत ही कम राहत देता है। उदाहरण के लिए, पहले से ही दिए गए 5 किलो चावल/गेहूं के अतिरिक्त, प्रति व्यक्ति और 5 किलो पीडीएस के माध्यम से मुफ्त दिया जायेगा।

स्थानों पर प्रतिबंधों को देखते हुए, संचालन और क्रियान्वयन के मुद्दे हो सकते हैं। गरीबों के लिए नकदी समय की मांग है, जो तीन सप्ताह के लॉकडाउन से बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। जबकि केन्द्र ने महिलाओं के जन धन खातों में नकद अंतरण की घोषणा की है, लेकिन यह जन धन के तहत केवल आधे लाभार्थियों को कवर करता है। पीएम किसान के तहत 2000 रूपये का भुगतान केवल बजट में पहले से निर्धारित लाभ का अग्रभार है और यह कोई नई राहत नहीं है।

इसके अलावा, मनरेगा के तहत दैनिक मजदूरी में 182 रूपये से 202 रूपये तक की वृद्धि, संगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए ईपीएफ निकासी की अनुमति देना और स्व–सहायता समूहों के लिए संपार्श्विक–मुक्त ऋण सीमा को रू0 20 लाख तक दोगुना करना, गरीब वर्गों पर कोविड–19 के प्रभाव का समाधान करने में सतह को नाममात्र को खुरचने जैसा है। योजना छोटे व्यवसायों के लिए कोई राहत नहीं देती है, जो एक बड़ी निराशा है।

भारत में, सरकार ने पहले स्वास्थ्य संरचना के लिए 15,000 करोड़ रूपये (जीडीपी का लगभग 0.1 प्रतिशत) की घोषणा की थी। राज्य स्तर पर कुछ प्रोत्साहन उपायों की घोषणा की गई है, केरला में 20,000 करोड़ रूपये (राज्य की जीडीपी का 2.5 प्रतिशत) का सबसे बड़ा पैकेज है, जिसमें गरीब परिवारों के लिए कुछ प्रत्यक्ष अंतरण शामिल हैं। राष्ट्रीय स्तर पर, कई क्षेत्रों में कर अनुपालन बोझ को आसान करने के लिए कई उपायों की घोषणा पहले ही की गई थी।

गुरूवार को घोषित रू0 1.7 लाख करोड़ के राहत पैकेज सहित, सरकार द्वारा किए गए उपाय स्पष्ट रूप से अन्य देशों द्वारा किए गए उपायों से कम हैं – परिमाण और लाभ की सीमा दोनों के संदर्भ में, विशेष रूप से दैनिक वेतन भोगियों, प्रवासी श्रमिकों और छोटे व्यवसायों के लिए।

कई देशों ने संकट से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन पैकेजों की घोषणा की है।

उदाहरण के लिए, अमेरिका में, स्वास्थ्य देखभाल, रूग्णावकाश, लघु व्यवसाय ऋण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए 8.3 बिलियन डॉलर के कोरोनावायरस प्रिपेयर्डनेस एंड रेस्पोंस सप्लीमेंटल एप्रोप्रिएशन एक्ट और 104 बिलियन डॉलर के फैमिलीज फर्स्ट कोरोनावायरस रेस्पोंस एक्ट (मिलाकर जीडीपी का 0.5 प्रतिशत) की घोषणा की गई है। सीनेट द्वारा 2–ट्रिलियन डॉलर (लगभग 10 प्रतिशत जीडीपी) का एक पैकेज भी पारित किया गया है।

चीन में, अनुमानित आरएमबी 1.3 ट्रिलियन (या जीडीपी का 1.2 प्रतिशत) के राजकोषीय उपायों को मंजूरी दी गई है। इसमें महामारी की रोकथाम, चिकित्सा उपकरणों का उत्पादन, बेरोजगारी बीमा के त्वरित संवितरण और कर राहत तथा सामाजिक सुरक्षा अंशदान माफी पर व्यय करना शामिल है।

इटली में, सरकार ने € 25–बिलियन (जीडीपी का 1.4 प्रतिशत) का आपातकालीन पैकेज अपनाया है, जिसमें नौकरियों को सुरक्षित रखने और नौकरी से निकाले गए कामगारों की समर्थन आय के उपाय और ऋण आपूर्ति का समर्थन करने के उपाय शामिल हैं जिसका उद्देश्य अन्य के साथ–साथ, व्यवसायों और परिवारों के लिए लगभग € 350 बिलियन (जीडीपी का 20%) की चलनिधि खोलना है।

लॉकडाउन उपायों के संभावित प्रभाव की भयावहता को देखते हुए, अब जो राहत की घोषणा की गई है, वह अत्यंत अपर्याप्त है और सरकार को इस पर विचार करना चाहिए तथा और अधिक राहत की घोषणा करनी चाहिए, विशेष रूप से गरीब वर्गों के लोगों की सुरक्षा के लिए।

अभिवादन सहित,

आपका साथी

ह...

सी.एच. वेंकटचलम्

महामंत्री